

[2023] 13 एस.सी.आर. 1049 : 2023 आईएनएससी 1029

**वाद का विवरण**

पावना दिब्बुर

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील संख्या 2779/2023)

29 नवंबर, 2023

[अभय एस. ओका और पंकज मित्तल, न्यायमूर्तिगण]

**शीर्ष टिप्पणियाँ**

**विचारणीय मुद्दा:** क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के अनुच्छेद 1 में शामिल भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के तहत अपराध को अनुसूचित अपराध के रूप में माना जा सकता है, भले ही कथित आपराधिक साजिश एक अपराध करने के लिए हो जो अनुसूची का हिस्सा नहीं है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - अनुसूची का अनुच्छेद 1 - दंड संहिता, 1860 - धारा 120 ख- अपीलकर्ता ने पहली संपत्ति एलायंस बिजनेस स्कूल से खरीदी और दूसरी संपत्ति आरोपी संख्या 1 से खरीदी, जिसके खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने खुद को एलायंस यूनिवर्सिटी का चांसलर बताकर छात्रों से 107 करोड़ रुपये एकत्र किए - चार प्रथम सूचना रिपोर्ट, ईसीआईआर दर्ज- अपीलकर्ता- अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने प्रवेश किया था आरोपी संख्या 1 के लाभ के लिए उसके नाम पर पहली और दूसरी संपत्तियों के नाममात्र बिक्री कार्यों को निष्पादित करके आरोपी संख्या 1 के साथ साजिश में शामिल होना और उसे विश्वविद्यालय के धन को हड़पने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करना, अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में उसकी सहायता करना- अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को रद्द करने की याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई

-अपीलकर्ता ने दलील दी कि चार अनुसूचित/विधेयक अपराधों में से, वाद में आरोप पत्र दायर किए गए थे। तीन अपराधों में से जिनमें धन शोधन निवारण अधिनियम, की अनुसूची में शामिल केवल एक अपराध का उल्लेख किया गया था - इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अकेले भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख , किसी अन्य अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति में, धन शोधन निवारण अधिनियम, के तहत आरोप को कायम नहीं रख सकती है और जब तक किसी अनुसूचित अपराध को करने की साजिश के संबंध में कोई आरोप नहीं है, धन शोधन निवारण अधिनियम,के तहत अभियोजन झूठ नहीं बोल सकता है:

**अभिनिर्धारित:** भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा जब कथित साजिश एक ऐसे अपराध को करने की हो जो विशेष रूप से अनुसूची में शामिल है - वर्तमान वाद में, कथित अनुसूचित अपराधों के लिए दायर आरोपपत्रों में, अनुसूची में शामिल किसी भी अपराध को करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का कोई आरोप नहीं है - भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख को छोड़कर, अनुसूची में कोई अन्य अपराध नहीं है। लागू किया गया था - इसलिए, इस वाद में, अनुसूचित अपराध बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है- इसलिए, अपीलकर्ता पर धारा 3, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है- विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया- धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष लंबित शिकायत, बेंगलुरु को वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में खारिज कर दिया गया - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482। [अनुच्छेद 26,27]

**धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 3 - अपीलकर्ता की दलील है कि चूंकि उसे कथित अनुसूचित अपराधों से संबंधित दायर आरोपपत्रों में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया था, इसलिए उसे धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है:**

**अभिनिर्धारित:** किसी दिए गए वाद में, यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन सभी आरोपियों के बरी होने पर समाप्त होता है या सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया जाता है या अनुसूचित अपराध की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है, तो अनुसूचित अपराध मौजूद नहीं होगा, और इसलिए, किसी पर भी धन शोधन निवारण अधिनियम की

धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि अपराध की कोई कार्यवाही नहीं होगी- इस प्रकार, ऐसे वाद में, वह आरोपी जिसके खिलाफ शिकायत है धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज किए गए अनुसूचित अपराध से सभी आरोपियों को बरी करने या रिहा करने से लाभ होगा- इसी तरह, उसे अनुसूचित अपराध की कार्यवाही को रद्द करने का लाभ मिलेगा- हालांकि, धन शोधन निवारण अधिनियम वाद में एक आरोपी जो अनुसूचित अपराध के बाद अपराध की आय को छुपाने या उपयोग करने में सहायता करके तस्वीर में आता है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है- ऐसा आरोपी अभी भी हो सकता है जब तक अनुसूचित अपराध मौजूद है, तब तक धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है- अनुसूचित अपराध होने के बाद धारा 3 के तहत अपराध किया जा सकता है- यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 3 के तहत अपराध का आरोप है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो - अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई। [अनुच्छेद 15,16]

**कानून की व्याख्या- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - अनुसूची का अनुच्छेद 1 - दंड संहिता, 1860 - धारा 120 ख:**

**अभिनिर्धारित:** दंडात्मक कानूनों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है- दंडात्मक कानूनों को विधायी इरादे के अनुसार समझा जाना चाहिए जैसा कि अधिनियम में व्यक्त किया गया है- विधायिका के इरादे को प्रभावी करते हुए, यदि दंडात्मक कानून के एक विशेष प्रावधान के लिए दो उचित व्याख्याएं दी जा सकती हैं, तो न्यायालय को आम तौर पर उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो दंडात्मक परिणामों को लागू करने से बचाती है - दोनों की अधिक उदार व्याख्या को अपनाने की आवश्यकता है- विधायी इरादे की भावना को एकत्र किया जा सकता है धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (ब) के तहत अनुसूचित अपराध का नियम यह है कि प्रत्येक अपराध जो अपराध की आय उत्पन्न कर सकता है, उसे अनुसूचित अपराध होने की आवश्यकता नहीं है- इसलिए, केवल कुछ विशिष्ट अपराधों को अनुसूची में शामिल किया गया है- इस प्रकार, यदि प्रवर्तन निदेशालय की प्रस्तुति है कि धारा 120 बी के रूप में, भारतीय दंड संहिता को अनुसूची के भाग ए में शामिल किया गया है, भले ही आरोप एक अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का हो जो इसका हिस्सा नहीं है अनुसूची, अपराध एक अनुसूचित अपराध बन जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, अनुसूची निरर्थक या निरर्थक हो जाएगी - कारण समझाया गया- प्रवर्तन

निदेशालय द्वारा सुझाई गई व्याख्या केवल कुछ चयनित अपराधों को अनुसूचित अपराध बनाने के विधायी उद्देश्य को विफल कर देगी- यदि ऐसी व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिकता के दोष को आकर्षित कर सकता है- आवेदन करके अनुसूची में शामिल नहीं किए गए हर अपराध को अनुसूचित अपराध बनाना विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है धारा 120 ख- इसलिए, अनुसूची के भाग क में शामिल धारा 120 बी के तहत अपराध केवल तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा यदि आपराधिक साजिश अनुसूची के भाग क , ख या ग में पहले से ही शामिल किसी अपराध को करने के लिए है। [अनुच्छेद 23-25]

### उद्धरणों और अन्य सन्दर्भों की सूची

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929 - संदर्भित।

### विवादित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य वाद का विवरण

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2779/2023

सीआरएलपी संख्या 3542/2022 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2022 से।

### अधिवक्तागण:

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री आशिमा मंडला, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, सुश्री अंकिता चौधरी, अधिवक्ता, अपीलकर्ता(ओं) के लिए।

एस. वी. राजू, एएसजी, मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री अलका अग्रवाल, अन्नम वेंकटेश, सुश्री सायरिका राजू, ज़ोहेब हुसैन, सलाहकार, प्रतिवादी के लिए।

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

## निर्णय

अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति

### सिंहावलोकन

1. प्रतिवादी- प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में, 'प्रवर्तन निदेशालय'), ने बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'धन शोधन निवारण अधिनियम') की धारा 45(1) के दूसरे प्रावधान के तहत एक शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत में अपीलकर्ता- पावना दिब्बुरको आरोपी संख्या 6 के रूप में दिखाया गया था। 17 मार्च 2022 के आदेश से विशेष न्यायालय ने उक्त शिकायत पर संज्ञान लिया। अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में, 'दंड प्रक्रिया संहिता') के तहत बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। उक्त शिकायत को रद्द करने की राहत की मांग कर रही है। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 द्वारा शिकायत निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी गई है।

2. वर्ष 2011 में, एलायंस बिजनेस स्कूल (संक्षेप में, 'एबीएस') ने 13.05 करोड़ रुपये में गोल्लाहल्ली गांव, जिगनी होबली, अनेकल तालुक, बेंगलुरु में खाता संख्या 37/22 वाली एक संपत्ति खरीदी। उक्त संपत्ति का क्षेत्रफल लगभग पांच एकड़ है। सुविधा के लिए, हम उक्त संपत्ति को 'पहली संपत्ति' के रूप में वर्णित कर रहे हैं। 1 जुलाई 2013 को, अपीलकर्ता ने 13.5 करोड़ रुपये के प्रतिफल के लिए एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा एबीएस से पहली संपत्ति खरीदी। आरोपी संख्या 1- मधुकर अंगुर ने कर्पुर गांव, कसाबा होबली, अनेकल तालुक, बेंगलुरु में सर्वे संख्या 61, 62 और 63 वाली 4 एकड़ और 0.4 गुंटा की संपत्ति खरीदी। सुविधा के लिए, हम इस संपत्ति को 'दूसरी संपत्ति' के रूप में वर्णित कर रहे हैं। अपीलकर्ता ने 29 जून 2019 को आरोपी संख्या 1 मधुकर अंगुर से 2.47 करोड़ रुपये में पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा दूसरी संपत्ति खरीदी।

3. पांच साल की अवधि के लिए, यानी 2010 से 2015 तक, अपीलकर्ता के पति- डॉ अयप्पा डोरे, एलायंस यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। अपीलकर्ता ने कुछ समय के लिए एलायंस यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी काम किया। 11 नवंबर 2017 को, एलायंस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की शिकायत पर आरोपी संख्या 1 मधुकर अंगुर के खिलाफ प्रथम सूचना

रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट ) दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने खुद को एलायंस यूनिवर्सिटी का चांसलर बताकर छात्रों से 107 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की। आरोप था कि उन्होंने जनवरी 2017 से नवंबर 2017 के बीच उक्त राशि एकत्रित की, जिसे श्रीवारी एजुकेशन सर्विसेज के खाते में जमा कराया गया. इसके बाद आरोपी संख्या 1 के खाते में करोड़ों रुपये हस्तांतरित किए गए।

4. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को आरोपी संख्या 1, 2 और 3, मधुकर अंगुर, उनकी पत्नी प्रियंका अंगुर और श्री रविकुमार, पार्टनर, श्रीवारी एजुकेशन सर्विसेज और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध का आरोप लगाते हुए एक प्रवर्तन वाद की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई थी। ईसीआईआर चार प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट ) संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट में धाराएं	आरोप पत्र	धाराएं जिसके तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया
1.	119/2016 (थाना जयप्रकाश नगर)	भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 420 और 506	ख- प्रतिवेदन दाखिल की गई/समापन प्रतिवेदन दिनांक 02/02/2017 को दाखिल किया गया।	समापन प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया।
2.	730/2016 (थाना मदीवाला)	143, 144, 147, 148, 149, 506 और 120-ख भारतीय दंड	आरोप पत्र दिनांक 04/07/2017 को दाखिल	आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धाराएं 143, 144, 147, 148, 149, 506 और 120 ख के अंतर्गत दाखिल

		संहिता की धाराएं	किया गया जिसमें अपीलकर्ता का नाम शामिल नहीं था।	की गई।
3.	52/2017 (थाना शंकरपुरा)	143, 144, 147, 148, 149, 506 और 120-ख भारतीय दंड संहिता की धाराएं	आरोप पत्र दिनांक 025/03/2018 को दाखिल किया गया जिसमें अपीलकर्ता का नाम शामिल नहीं था।	आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धाराएं 504, 506, 120-ख सह पठित धारा 34 के अंतर्गत दाखिल की गई।
4.	188/2017	143, 406, 407, 408, 409 और 149 भारतीय दंड संहिता की धाराएं	आरोप पत्र दिनांक 18/06/2019 को दाखिल किया गया जिसमें अपीलकर्ता का नाम शामिल नहीं था।	आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धाराएं 406, 408, 408, 447, 204, 120-ख सह पठित धारा 34 के अंतर्गत दाखिल की गई।

5. 27 सितंबर 2021 को, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत पहली और दूसरी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया। दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें अपीलकर्ता को पांचवें प्रतिवादी के रूप में दिखाया गया है।

6. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45(1) के दूसरे प्रावधान के तहत दायर शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने आरोपी संख्या 1 के लाभ के लिए

उसके नाम पर पहली और दूसरी संपत्तियों के संबंध में नाममात्र बिक्री कार्य निष्पादित करके आरोपी संख्या 1- मधुकर अंगुर के साथ साजिश रची है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि अपीलकर्ता ने आरोपी संख्या 1 को विश्वविद्यालय के धन को निकालने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करने की सुविधा दी, जिससे अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में आरोपी संख्या 1 की सहायता की गई। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य<sup>1</sup>** के वाद में इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

### **अपीलकर्ता की प्रस्तुतियाँ**

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि पहली और दूसरी संपत्ति दागी संपत्ति नहीं है और इसलिए, वे धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (प) के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि पहली संपत्ति पहली अनुसूचित अपराध से काफी पहले 1 जुलाई 2013 को अर्जित की गई थी। 11 नवंबर 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी संख्या 1 के खिलाफ आरोप यह है कि उसने जनवरी और नवंबर 2017 के बीच छात्रों से लगभग 107 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की और स्थानांतरित कर दी। उक्त राशि उसके खाते में। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा पहली संपत्ति के अधिग्रहण को अनुसूचित अपराध के संबंध में अपराध की आय से कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। उसने प्रस्तुत किया कि दूसरी संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में, अपीलकर्ता के पास इसे हासिल करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन उपलब्ध थे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आय घोषणा योजना, 2016 के तहत अपीलकर्ता के नेतृत्व में आयकर रिटर्न पर भरोसा किया, जिसके द्वारा उसने 26,42,54,193/- रुपये की कुल अघोषित आय घोषित की। अपीलकर्ता ने 8 सितंबर 2016 को आयकर और जुर्माने के रूप में 11,89,08,385/- रुपये का भुगतान किया। रिटर्न 12 सितंबर 2016 को दाखिल किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता के पास 2.47 करोड़ रुपये की दूसरी संपत्ति प्राप्त करने के लिए धन का स्रोत था। अपीलकर्ता द्वारा अर्जित दोनों संपत्तियों का अनुसूचित अपराधों की आय से कोई संबंध नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि 2.47 करोड़ रुपये पर सहमति हुई थी, क्योंकि बिक्री विलेख में उल्लेख किया गया है कि यह आरोपी संख्या 1- मधुकर अंगुर द्वारा की गई एक संकटकालीन बिक्री थी।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का दूसरा पहलू यह है कि चूंकि अपीलकर्ता को कथित अनुसूचित अपराधों से संबंधित आरोपपत्रों में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है, इसलिए उसे धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने **विजय मदनलाल चौधरी<sup>1</sup>** के वाद में इस न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 251 से 253 में दी गई बातों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि फैसले में, इस अदालत ने माना कि यदि अनुसूचित/घातक अपराध में किसी आरोपी को बरी/बरी कर दिया जाता है, तो उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता का मामला बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसे किसी भी अनुसूचित/अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में भी नहीं दिखाया गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेगी कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं लिया जा सकता था।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की तीसरी दलील यह है कि चार अनुसूचित/अनुसूचित अपराधों में से, तीन अपराधों के वाद में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, और इन आरोप पत्रों में, धन शोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची में शामिल केवल एक अपराध का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख है। उन्होंने बताया कि 2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119 और 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 शामिल की गई थी। हालाँकि, 2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119 में, समापन प्रतिवेदन दायर की गई थी, और 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52 में, आरोप पत्र दाखिल करते समय, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को बाहर रखा गया था। उसने इसका विरोध किया। अकेले भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, किसी अन्य अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति में, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप को कायम नहीं रख सकती है। जब तक किसी अनुसूचित अपराध को अंजाम देने की साजिश के संबंध में कोई आरोप न हो, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन झूठ नहीं बोल सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के प्रावधान पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अवैध तरीकों से किया गया कोई अवैध कार्य या कानूनी कार्य, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत साजिश के अपराध को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है। यदि भारतीय दंड संहिता की

धारा 120- ख को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन आकर्षित करने के लिए एक स्वतंत्र अपराध के रूप में माना जा सकता है, तो उस तर्क से, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक शिकायत दायर की जा सकती है जहां आरोप एक अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का है जो एक अनुसूचित अपराध नहीं है। इसलिए, उनका कहना है कि अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत रद्द की जानी चाहिए।

### प्रतिवादी की प्रस्तुतियाँ

10. श्री एस.वी. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता के पास दूसरी संपत्ति हासिल करने की मौद्रिक क्षमता है, कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि आरोपी संख्या 1 द्वारा छिनी गई धनराशि, जो अपराध की आय है, का उपयोग अपीलकर्ता द्वारा दूसरी संपत्ति हासिल करने के लिए नहीं किया गया था। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर केवल सुनवाई के समय ही विचार किया जा सकता है। दूसरे निवेदन के संबंध में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसे विधेय अपराध में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि किसी दिए गए वाद में, एक व्यक्ति जो विधेय अपराध में आरोपी नहीं है, वह धन शोधन का अपराध कर सकता है। तीसरे निवेदन के संबंध में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जहां भी विधायिका का इरादा था, उसने एक विशेष अपराध को दूसरे अपराध के साथ अनुसूचित अपराध के रूप में पढ़ा है। उन्होंने हमारा ध्यान धन शोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची के भाग ए के अनुच्छेद 4 और 6 की ओर आकर्षित किया। धन शोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 11 का उल्लेख करते हुए, उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद 4 में पहले चार अपराध और अनुच्छेद 6 में सभी अपराध विधायिका की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूची को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वह है, और धन शोधन निवारण अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसूची में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि **विजय मदनलाल चौधरी**<sup>1</sup> के वाद में अनुसूची की वैधता को बरकरार रखा गया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

## प्रस्तुतियों पर विचार

अपीलकर्ता का प्रभाव जानबूझकर किए गए अपराध में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है।

11. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

"3. धन शोधन का अपराध- जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्ज़ा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

**स्पष्टीकरण.**-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल है, अर्थात्:-

(ए) छिपाना; या

(बी) कब्ज़ा; या

(सी) अधिग्रहण; या

(डी) उपयोग; या

(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या

(च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना,

किसी भी प्रकार से;

(ii) "अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छुपाकर या कब्जे या अधिग्रहण या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके इसका आनंद ले रहा है।"

धारा 3 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, जब तक अपराध की आय मौजूद न हो, कोई धन शोधन अपराध नहीं हो सकता है। उपधारा का खंड (प) धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 का (1) "अपराध की आय" को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है:

**"2. परिभाषा -** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

.....  
(प) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी जाती है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के मूल्य के बराबर संपत्ति;

**स्पष्टीकरण.-**संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है।"

12. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) का खंड (फ) "संपत्ति" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है हर विवरण की कोई भी संपत्ति या संपत्ति, चाहे वह भौतिक हो या निराकार, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त। किसी भी संपत्ति को अपराध की आय के रूप में गठित करने के लिए, इसे किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है। खंड (प) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी

किसी भी संपत्ति का मूल्य भी अपराध की आय होगी। इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए "अपराध की आय" का अस्तित्व अनिवार्य है।

13. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) का खंड (भ) "अनुसूची" को परिभाषित करता है। इसका खंड (ब) "अनुसूचित वाद " को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है:

"2. परिभाषा - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -  
(ब) "अनुसूचित वाद " का अर्थ है-

(i) नीचे निर्दिष्ट अपराध अनुसूची का भाग क; या

(ii) अनुसूची के भाग ख के तहत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य एक करोड़ रुपये या अधिक है; या

(iii) अनुसूची के भाग ग के तहत निर्दिष्ट अपराध।

14. अपराध की आय के अस्तित्व के लिए पूर्व शर्त एक अनुसूचित अपराध का अस्तित्व है। इस पहलू पर, **विजय मदनलाल चौधरी**<sup>1</sup> के वाद में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 253 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"253. संक्षेप में कहें तो यह केवल ऐसी संपत्ति है जो किसी अनुसूचित संपत्ति से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जाती है, उसे अपराध की आय माना जा सकता है। 2002 के अधिनियम के तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन के लिए इस धारणा पर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते हैं कि उनके द्वारा बरामद की गई संपत्ति अपराध की आय होनी चाहिए और यह कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि यह अधिकार क्षेत्र की पुलिस में दर्ज नहीं है या सक्षम मंच के समक्ष शिकायत के माध्यम से जांच लंबित है। क्योंकि, "व्युत्पन्न या प्राप्त" अभिव्यक्ति पहले से ही पूरा किए गए अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का संकेत है। इसी प्रकार, यदि किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में

नामित व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा आरोपमुक्त करने, दोषमुक्त करने के आदेश के कारण या उसके खिलाफ आपराधिक वाद (अनुसूचित अपराध) को रद्द करने के कारण दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जो कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति के संबंध में उसके माध्यम से दावा करता है। केवल इस व्याख्या को 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, विशेष रूप से धारा 2 (1) (प)को धारा 3 के साथ पढ़ा जा सकता है। कोई अन्य दृष्टिकोण रखना इन प्रावधानों को फिर से लिखना होगा और अवज्ञा खंड "अपराध की आय" की व्यक्त भाषा की अवहेलना करना होगा, जैसा कि अभी तक प्राप्त होता है।

(रेखांकित किया गया)

अनुच्छेद 269 और 270 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"269. 2002 के अधिनियम की धारा 3 की खुली भाषा से यह स्पष्ट है कि धन शोधन का अपराध अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था। प्रक्रिया या गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है- चाहे वह छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने, अपराध की आय का उपयोग करने के लिए हो, जितना कि इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना। इस प्रकार, अपराध की आय से जुड़ी ऐसी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना धन शोधन का गठन करेगा। इस अपराध का अन्यथा किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है-सिवाय उस अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त अपराध की आय के।

270. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि केवल आपराधिक गतिविधि (एक अनुसूचित अपराध) के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त होने या प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है। यह अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने या सहायता करने या पक्षकार होने के लिए धन शोधन का एक कारण होगा; और किसी दिए गए तथ्य की स्थिति में ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर कारण हो सकती है, चाहे निर्धारित अपराध की तारीख और समय कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में,

आपराधिक गतिविधि इससे पहले की जा सकती है जिसे 2002 के अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त अपराध की आय से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त रहा है या जारी रहा है, तो 2002 के अधिनियम के तहत धन शोधन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है- अपराध की आय (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) रखने या छिपाने के लिए या उसका कब्जा बनाए रखने के लिए या पूरी तरह से समाप्त होने तक खाइयों में इसका उपयोग करने के लिए। धन-शोधन का कार्य उस तारीख पर निर्भर नहीं है या उससे जुड़ा नहीं है जिस पर निर्धारित कार्य किया गया है या यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो कार्य किया गया है। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर व्यक्ति अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। ये सामग्री मूल प्रावधान (धारा 3, जैसा कि संशोधित किया गया है) में आंतरिक हैं। 2013 तक और दिनांक 31.7.2019 तक प्रभावी थे) और इसे केवल वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019। इस प्रकार समझा जाता है कि 2019 में अंतःस्थापित स्पष्टीकरण में खंड (ii) को शामिल करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह धारा 3 के दायरे को बिल्कुल भी परिवर्तित या विस्तारित नहीं करता है।

(रेखांकित किया गया)

15. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 पर वापस आते हुए, इसके सादे पढ़ने पर, धारा 3 के तहत एक निर्धारित ऑफेंस प्रतिबद्ध होने के बाद किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आइए हम एक ऐसे व्यक्ति का मामला लेते हैं जो अनुसूचित अपराध से असंबद्ध है, जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में सहायता करता है या जानबूझकर अपराध की आय के उपयोग में सहायता करता है। उस वाद में, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। एक ठोस उदाहरण देने के लिए, "जबरन वसूली" से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 384 से 389 के तहत अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 1 में शामिल किए गए हैं। एक अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 384 से 389 के अंतर्गत जबरन वसूली और धन उगाही का अपराध कर सकता है। इसके बाद, जबरन वसूली से असंबद्ध व्यक्ति जबरन वसूली की आय को छिपाने में उक्त अभियुक्त की सहायता कर सकता है। ऐसे वाद में, जो व्यक्ति जबरन वसूली के अपराध की आय को छिपाने के लिए अभियुक्त की सहायता करता है, वह धन शोधन का दोषी हो सकता है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके

खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया होगा। **विजय मदनलाल चौधरी**<sup>1</sup> के वाद में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 270 में जो कहा गया है, वह उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें यह हैं कि एक अनुसूचित अपराध होना चाहिए और अनुसूचित अपराध के संबंध में अपराध की आय होनी चाहिए जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (प) में परिभाषित किया गया है।

16. किसी वाद में, यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन सभी अभियुक्तों को बरी करने या सभी अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने में समाप्त हो जाता है या अनुसूचित अपराध की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है, तो अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं होगा, और इसलिए, किसी पर भी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि अपराध की कोई आय नहीं होगी। इस प्रकार, ऐसे वाद में, जिस अभियुक्त के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की गई है, वह सभी अभियुक्तों को बरी करने या आरोपमुक्त करने से समाप्त होने वाले अनुसूचित अपराध से लाभान्वित होगा। इसी तरह, उसे निर्धारित कार्यवाही को रद्द करने का लाभ मिलेगा। हालांकि, धन शोधन निवारण अधिनियम वाद में एक आरोपी जो अपराध की आय को छिपाने या उपयोग करने में सहायता करके निर्धारित अपराध के बाद सामने आता है, उसे निर्धारित अपराध में आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभियुक्त पर तब तक धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक कि निर्धारित समय सीमा मौजूद है। इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस आधार पर उठाया गया दूसरा तर्क कि अपीलार्थी को आरोपपत्रों में अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था, जिसे खारिज किया जाना चाहिए।

### **प्रथम और द्वितीय संपत्ति की प्राप्ति**

17. शिकायत में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने करोड़ों की संपत्ति खरीदी, हालांकि उसके पास आय का स्रोत नहीं था जो विषय संपत्तियों को खरीदने के लिए पर्याप्त

धन उत्पन्न कर सके। अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने आरोपी संख्या 1-मधुकर अंगुर को अपने बैंक खाते का उपयोग करके गबन/गबन की गई राशि को छिपाने की अनुमति दी और सुविधा प्रदान की। एक अन्य आरोप यह है कि उसने आरोपी संख्या 1 से दूसरी संपत्ति खरीदी है, हालांकि उसके पास प्रतिफल का भुगतान करने के लिए संसाधन नहीं थे। आरोप यह है कि उसने आरोपी संख्या 1 को अपराध की आय की हेराफेरी करने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करने की अनुमति दी। एक अन्य आरोप यह है कि प्रथम और द्वितीय दोनों संपत्तियों का अधिग्रहण अपराध की आय से किया गया है। प्रथम संपत्ति, पूर्व रूप से, को अपराध की आय के साथ कोई संबंध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अनुसूचित संपत्ति का गठन करने वाले कार्य इसके अधिग्रहण के बाद हुए थे। अपीलार्थी का मामला यह है कि उसके पास पर्याप्त राशि थी, जैसा कि सितंबर 2016 में आय घोषणा योजना, 2016 के तहत उसके द्वारा की गई घोषणा से देखा जा सकता है और इसलिए, दूसरी संपत्ति के अधिग्रहण के समय, दूसरी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उसके पास पर्याप्त धन उपलब्ध था। यह मुद्दा कि क्या अपीलार्थी ने दूसरी संपत्ति हासिल करने के लिए दागी धन का इस्तेमाल किया, सबूत पेश किए जाने के बाद ही तय किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई हो कि बिक्री प्रतिफल का भुगतान अपीलार्थी के किसी विशेष बैंक खाते से किया गया था। इसलिए, इस स्तर पर एक खोज दर्ज करना संभव नहीं है कि दूसरी संपत्ति अपराध की आय का उपयोग करके अर्जित नहीं की गई थी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मुद्दे पर केवल विचार किया है धन शोधन निवारण अधिनियम की प्रयोज्यता का संदर्भ। हमने बिक्री विलेखों के मूल्यांकन और वैधता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है।

### **अनुसूची के अनुच्छेद 1 में पहली प्रविष्टि की व्याख्या**

18. अब, हम अनुसूची की व्याख्या के आधार पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए तीसरे तर्क पर आते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विजय मदनलाल चौधरी<sup>1</sup> के वाद में, अनुसूची की वैधता भी चुनौती के दायरे में थी। उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय को अनुसूची में किसी भी प्रविष्टि की व्याख्या करने के लिए नहीं कहा गया था और विशेष रूप से, अनुसूची में धारा 120-ख की प्रविष्टि। अनुसूची की चुनौती पर उक्त निर्णय के अनुच्छेद 453, 454 और 455 में चर्चा की गई है। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि छोटी राशि को भी अनुसूची में शामिल

किया गया है, और यहां तक कि शमनीय राशि को भी अनुसूची का हिस्सा बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जिन वस्तुओं का सीमा पार प्रभाव नहीं है, उन्हें अनुसूची में शामिल किया गया है। उक्त विनिश्चय के अनुच्छेद 454 और 455 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"454. इस अनुसूची को 2009 के अधिनियम 21, 2013 के अधिनियम 2, 2015 के अधिनियम 22, 2018 के अधिनियम 13 और 2018 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित किया गया है। चुनौती अनुसूची के अधिनियमन और समय-समय पर उसके संशोधनों के संबंध में विधायी क्षमता के आधार पर नहीं है। हालांकि, हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि इस दृष्टिकोण में कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि इसमें धन शोधन के उद्देश्यों के लिए निर्धारित ऑफ-एनस के रूप में मामूली ऑफ-एनस भी शामिल हैं, विशेष रूप से ऑफ-एनस जिनका कोई सीमा पार प्रभाव नहीं है और पक्षों के बीच कंपाउंडेबल हैं। धन शोधन के गठन के लिए समान रूप से प्रासंगिक मानने के लिए वर्गीकरण या समूह बनाना विधायी नीति का विषय है। संसद ने अपने विवेक में विशिष्ट आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त संपत्ति को अनुसूची में उल्लिखित संबंधित विधान के तहत एक अपराध माना है। तथ्य यह है कि कुछ अपराध संबंधित विधान के अधीन गैर-संज्ञेय हो सकते हैं या मामूली और शमनीय माने जा सकते हैं, फिर भी, संसद ने अपने विवेक में ऐसी आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि के संचयी प्रभाव को देश की आर्थिक स्थिरता, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की संभावना के रूप में माना है और इस प्रकार, इसे धन-शोधन के अपराध के रूप में मानने के लिए उन्हें एक साथ समूहीकृत किया है, यह विधायी नीति का विषय है। इस तरह की नीति पर दूसरा अनुमान लगाना न्यायालय के लिए खुला नहीं है।

455. यह रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि 2002 के अधिनियम का उद्देश्य धन-शोधन गतिविधि के संबंध में कार्रवाई शुरू करना है जो आवश्यक रूप से किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त संपत्ति से जुड़ी है। इस अधिनियम के तहत अभियोजन आपराधिक गतिविधि के संबंध में नहीं है, बल्कि विशिष्ट आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति तक सीमित है। नतीजतन, आपराधिक गतिविधि को शामिल करना, जिसे संबंधित कानून के तहत गैर-संज्ञेय, शमनीय या मामूली अपराध माना गया है, का मुद्दे में वाद का जवाब देने के लिए कोई

असर नहीं होना चाहिए। इसमें, धन शोधन का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है और इस तरह के अपराध में शामिल व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत एक साथ समूहबद्ध किया जाता है। जहाँ तक धन शोधन का संबंध है, उनके बीच अंतर करने का कोई कारण नहीं है। हमारी राय में, इसलिए, विचाराधीन तर्क में कोई योग्यता नहीं है।“

इस वाद में, हमें अनुसूची या उसके किसी भाग की वैधता तय करने के लिए नहीं कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या अनुसूची के अनुच्छेद 1 में शामिल भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत अपराध को अनुसूचित अपराध के रूप में माना जा सकता है, भले ही कथित आपराधिक साजिश एक अपराध करने के लिए हो जो अनुसूची का हिस्सा नहीं है। **विजय मदनलाल चौधरी**<sup>1</sup> के वाद में यह मुद्दा विचार के लिए नहीं उठा था।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 120क "आपराधिक साजिश" की अवहेलना करती है, जो इस प्रकार है:

**"120क आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा-** जब दो या दो से अधिक व्यक्ति करने के लिए सहमत होते हैं, या करने का कारण बनते हैं, -

(1) कोई अवैध कार्य, या

(2) एक कार्य जो अवैध साधनों से अवैध नहीं है, ऐसे समझौते को आपराधिक षड्यंत्र नामित किया जाता है:

बशर्ते कि अपराध करने के समझौते के अलावा कोई भी समझौता आपराधिक साजिश के बराबर नहीं होगा जब तक कि समझौते के अलावा कुछ कार्य ऐसे समझौते के एक या अधिक पक्षों द्वारा उसके अनुसरण में नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अवैध कार्य इस तरह के समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस उद्देश्य के लिए आकस्मिक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान करती है जो इस प्रकार है:

**"120 ख आपराधिक षड्यंत्र की सजा-** (1) जो कोई भी मौत, आजीवन कारावास या दो वर्ष या

उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार है, जहां इस संहिता में ऐसे षड्यंत्र की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध को बढ़ावा दिया था।

(2) जो कोई भी ऊपर बताए गए दंडनीय अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के अलावा किसी आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार है, उसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास, या दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

20. अब, हम धन शोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची की ओर मुड़ते हैं। हम समझते हैं कि कई अपराध, जो अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं, को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हम केवल चित्रण के माध्यम से ऐसे कुछ ऑफ एनसेस का उल्लेख कर रहे हैं:

**क.** धर्तीय दंड संहिता की धारा 263, जो विशिष्ट मुद्रांक बनाने या रखने से संबंधित है, अनुसूची का हिस्सा नहीं है;

**ख.** हालांकि डकैती और डकैती के संबंध में धारा 392 से 402 के तहत दंडनीय अपराधों को अनुसूची के भाग क में शामिल किया गया है, लेकिन चोरी करने की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध और एक आवासीय घर में चोरी की धारा 380 के तहत दंडनीय अपराध को अनुसूची के भाग क और ख का हिस्सा नहीं बनाया गया है। दोनों श्रेणियों की चोरी बहुत बड़ी राशि की हो सकती है जो करोड़ों में चल रही है। अनुसूची के भाग ग के खंड (3) के आधार पर उक्त दो अपराध केवल तभी अनुसूचित हो जाते हैं जब अपराध के सीमा पार निहितार्थ होते हैं;

**ग.** संपत्ति के बेईमानी के दुरुपयोग की धारा 403 के तहत दंडनीय अपराध अनुसूची का हिस्सा नहीं है। अनुसूची के भाग ग के खंड (3) के आधार पर उक्त अपराध केवल तभी अनुसूचित अपराध बन जाता है जब अपराध का सीमा पार प्रभाव होता है;

**घ.** आपराधिक विश्वासघात की धारा 405 के तहत अपराध, जो धारा 406 के तहत दंडनीय है, अनुसूची का हिस्सा नहीं है। अनुसूची के भाग ग के खंड (3) के आधार पर उक्त अप्रासंगिकता केवल तभी अनुसूचित अप्रासंगिकता बन जाती है जब अप्रासंगिकता के सीमा पार निहितार्थ हों;

ड. हालांकि धोखाधड़ी की धारा 417 के तहत अपराध को अनुसूचित अपराध बना दिया गया है, धारा 468 के तहत धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए जालसाजी का अधिक कठोर अपराध अनुसूची का हिस्सा नहीं है, और

च. हालांकि धारा 489ए से 489सी के तहत जाली नोट बनाने या जाली नोट बनाने का मामला अनुसूची का हिस्सा है, लेकिन धारा 489डी के तहत जाली नोट बनाने या नकली नोट बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाने या रखने का अपराध अनुसूची का हिस्सा नहीं है।

21. अब, अनुसूची के भाग ख पर आते हुए, इसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 के तहत केवल एक छूट शामिल है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ब) के उपखंड (ii) को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत झूठी घोषणा आदि करने का अपराध केवल तभी अनुसूचित अपराध बन जाता है जब अपराध में शामिल कुल मूल्य रूपे 1 करोड़ या उससे अधिक हो। अनुसूची के भाग ग में यह प्रावधान किया गया है कि भाग क में निर्दिष्ट कोई भी सीमा पार निहितार्थ भाग ग का हिस्सा बन जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत संपत्ति के खिलाफ सीमा पार निहितार्थ वाले सभी वाद अनुसूचित हो जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 379 (चोरी) 380 (घर में चोरी) 403 (संपत्ति का बेईमानी से गबन) और 405 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दंडनीय हैं। कहा गया है कि अपराध भाग क में शामिल नहीं हैं, वे भाग ग के आधार पर केवल तभी निर्धारित हो जाते हैं जब उनके सीमा पार निहितार्थ होते हैं। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि अपराध की आय उत्पन्न करने में सक्षम कई कार्य अनुसूची का हिस्सा नहीं हैं।

22. विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120- ख को अनुसूची के भाग ए में शामिल किया गया है, भले ही आरोप एक अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का हो जो अनुसूची का हिस्सा नहीं है, तो अपराध एक अनुसूचित अपराध बन जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत कई प्रावधान भाग ए और बी में शामिल नहीं हैं। वे केवल तभी निर्धारित हो जाते हैं जब उनके सीमा पार निहितार्थ होते हैं। इस प्रकार, संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग या विश्वास या चोरी के आपराधिक उल्लंघन एक अनुसूचित अपराध बन सकते हैं,

बशर्ते कि उनके सीमा पार निहितार्थ हों। इस प्रकार, संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग या विश्वास या चोरी के आपराधिक उल्लंघन एक अनुसूचित अपराध बन सकते हैं, बशर्ते कि उनके सीमा पार निहितार्थ हों। यदि विद्वत् अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क स्वीकार किया जाता है, यदि धारा 403 या धारा 405 के तहत अपराध करने की साजिश है, हालांकि इसका कोई सीमा पार निहितार्थ नहीं है, तो धारा 403 और 405 के तहत अपराध करने की साजिश की धारा 120- ख के तहत अपराध एक अनुसूचित अपराध बन जाएगा। इस प्रकार, यदि कोई अपराध अनुसूची के भाग क, ख और ग में शामिल नहीं है, लेकिन यदि अपराध करने की साजिश का आरोप लगाया जाता है, तो वह एक अनुसूचित अपराध बन जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध को भाग ख के तहत अनुसूचित अपराध बनाया जाता है, बशर्ते कि अपराध में शामिल मूल्य एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। लेकिन अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 120- ख लागू होती है, तो जो भी रुपए 1 लाख के मूल्य का अपराध करता है, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। उस तर्क के अनुसार, किसी भी दंडात्मक कानून के तहत कोई भी अपराध करने की साजिश, जो आय उत्पन्न करने में सक्षम है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 120- ख लागू करके अनुसूचित अपराध में परिवर्तित किया जा सकता है, हालांकि अपराध अनुसूची का हिस्सा नहीं है। यह विधायिका की मंशा नहीं हो सकती।

23. दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से अर्थ निकालने की आवश्यकता है। यह सच है कि दंडात्मक कानूनों का अर्थ विधायी इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए जैसा कि अधिनियम में व्यक्त किया गया है। जी. पी. सिंह के सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों (15वां संस्करण) के अध्याय में यह देखा गया है कि:

"विधायिका का इरादा, इस प्रकार, दो पहलुओं को आत्मसात करता है: एक पहलू में यह" अर्थ "की अवधारणा रखता है, यानी जो शब्दों का क्या अर्थ है और एक अन्य पहलू में, यह कानून के माध्यम से व्याप्त "उद्देश्य और उद्देश्य" या "कारण और भावना" की अवधारणा को व्यक्त करता है। इसलिए, निर्माण की प्रक्रिया शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण दोनों दृष्टिकोण को जोड़ती है। दूसरे शब्दों में विधायी आशय, जो, किसी अधिनियम का सही या कानूनी अर्थ किसी भी स्पष्ट उद्देश्य या उद्देश्य के प्रकाश में अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके प्राप्त किया जाता है जो शरारत और उसके उपचार को समझता है जिसके लिए अधिनियम निर्देशित किया जाता है। ड्राइजर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यू, द्वितीय

संस्करण, 1983 के शब्दों में: किसी अधिनियम के शब्दों को उनके संपूर्ण संदर्भ में और उनके व्याकरणिक और सामान्य अर्थों में अधिनियम की योजना, अधिनियम के उद्देश्य और संसद के आशय के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस सूत्रीकरण को बाद में सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी मिली और इसे "निर्माण का प्रमुख सिद्धांत" कहा गया। संवैधानिक और वैधानिक दोनों व्याख्याओं में, न्यायालय से कानून के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों के बीच उचित संबंध निर्धारित करने में विवेक का प्रयोग करने और कानून को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने की अपेक्षा की जाती है।

(जोर दिया गया)

24. विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाते समय, यदि दंडात्मक कानून के किसी विशेष प्रावधान की दो उचित व्याख्याएँ दी जा सकती हैं, तो न्यायालय को आम तौर पर ऐसी व्याख्या को अपनाना चाहिए जो दंडात्मक परिणामों को लागू करने से बचाती है। दूसरे शब्दों में, दोनों की अधिक उदार व्याख्या को अपनाने की आवश्यकता है।

25. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ब) के तहत अनुसूचित अपराध की अवज्ञा से जो विधायी आशय एकत्र किया जा सकता है, वह यह है कि प्रत्येक अपराध जो अपराध की आय उत्पन्न कर सकता है, उसे अनुसूचित अपराध होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, अनुसूची में केवल कुछ विशिष्टताओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार, यदि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो अनुसूची अर्थहीन या निरर्थक हो जाएगी। इसका कारण यह है कि भले ही पंजीकृत अनापत्ति एक अनुसूचित अनापत्ति नहीं है, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान और विशेष रूप से, धारा 3 को केवल धारा 120-ख को लागू करके लागू किया जाएगा। अगर हम धारा 120-ख को देखें, तो केवल इसलिए कि अपराध करने की साजिश है, ऐसा नहीं है एक गंभीर अपराध बन जाता है। इसका उद्देश्य अपराध करने की साजिश में शामिल लोगों को दंडित करना है, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया होगा जो अपराध का गठन करता हो। षड्यंत्र अभियुक्त के बीच अपराध करने के लिए एक समझौता है। यदि हम धारा 120-ख के तहत प्रदान किए गए दंडों को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक गंभीर अपराध नहीं है। इसमें केवल प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को शामिल किया गया है। यदि कानून में किसी विशेष अपराध को करने की साजिश के लिए कोई विशिष्ट सजा का

प्रावधान नहीं है, तो धारा 120-ख मुख्य आरोपी के साजिशकर्ता को सजा देने के उद्देश्यों के लिए उकसाने वाले के रूप में मानती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुझाई गई व्याख्या केवल कुछ चयनित अपराधों को निर्धारित अनुसूचित अपराधों के रूप में बनाने के विधायी उद्देश्य को विफल कर देगी। यदि हम ऐसी व्याख्या को स्वीकार करते हैं, तो कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए असंवैधानिकता के दोष को आकर्षित कर सकता है। यह विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है कि धारा 120-ख को लागू करके अनुसूची में शामिल नहीं किए गए प्रत्येक खंड को एक अनुसूचित खंड बनाया जाए। इसलिए, हमारे विचार में, अनुसूची के भाग क में शामिल भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत अपराध केवल तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा जब आपराधिक साजिश अनुसूची के भाग क, ख या ग में पहले से शामिल किसी भी अपराध को करना है। दूसरे शब्दों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा जब कथित साजिश एक अपराध करने का है जो अन्यथा एक अनुसूचित अपराध है।

26. वाद के तथ्यों पर वापस आते हुए, कथित अनुसूचित अपराधों में दायर आरोप पत्रों में, अनुसूची में शामिल किसी भी अपराध को करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का कोई आरोप नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख को छोड़कर, अनुसूची में कोई अन्य अपराध लागू नहीं किया गया है। इसलिए, इस वाद में, अनुसूचित अपराध बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

### **निष्कर्ष**

27. जबकि हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रचार की गई पहली और दूसरी दलीलों को अस्वीकार करते हैं, तीसरी दलीलों को बरकरार रखा जाना चाहिए। हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

क. यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया होगा;

**ख.** यहां तक कि अगर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शिकायत में दिखाया गया कोई आरोपी अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं है, तो भी उसे अनुसूचित अपराध में सभी अभियुक्तों को बरी करने या सभी अभियुक्तों को अनुसूचित अपराध में आरोपमुक्त करने से लाभ होगा। इसी प्रकार, उसे अनुसूचित संपत्ति की कार्यवाही को रद्द करने के आदेश का लाभ मिलेगा;

**ग.** प्रथम संपत्ति का अपराध की आय के साथ कोई संबंध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अनुसूचित संपत्ति का गठन करने वाले कार्य संपत्ति के अधिग्रहण के बाद किए गए थे;

**घ.** यह मुद्दा कि क्या अपीलार्थी ने दूसरी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अपराध की आय के हिस्से के रूप में दागी धन का उपयोग किया है, केवल मुकदमे के समय तय किया जा सकता है; और

**ङ.** भारतीय दंड संहिता की धारा 120- ख के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा जब कथित साजिश किसी अपराध को करने की हो जो अनुसूची में विशेष रूप से शामिल है।

**28.** तदनुसार, दिनांक 27 सितंबर 2022 का आक्षेपित आदेश, इसके द्वारा, रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है, और शिकायत 2022 का विशेष शिकायत संख्या 781 है जो धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के लिए विशेष न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष लंबित है, इसके द्वारा, केवल वर्तमान अपीलार्थी के संबंध में रद्द कर दिया गया है।

**29.** तदनुसार, अपील की अनुमति है।

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्य पांडे द्वारा तैयार की गईं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (मदन मोहन प्रिय) के द्वारा किया गया है।